



2026:AHC:64672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10537 / 2026

गोकरन राजपूत

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शाश्वत किशोर चतुर्वेदी

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शाश्वत किशोर चतुर्वेदी, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री उपेंद्र पाल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 437/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 238, 191(2), 3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - कोतवाली, जिला - महोबा में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में आवेदक का नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज होने के बावजूद, प्रश्नगत घटना के प्रत्यक्षदर्शी न होने के बावजूद, आवेदक के विरुद्ध आरोप संदेह के आधार पर लगाए गए हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना के पच्चीस दिन बाद मृतक की माता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उसने घटना को तब देखा था जब सभी अभियुक्त उसके बेटे को पीट रहे थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना के पच्चीस दिन बाद मृतक की माता का बयान दर्ज करना ही संदिग्ध है, जबकि प्रश्नगत घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं था और आवेदक के विरुद्ध कोई भी दोषी ठहराने वाले साक्ष्य नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अर्जुन और पवन को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5527/2026 और 5990/2026 क्रमशः मामले में आदेशों दिनांक 24.02.2026 और 26.02.2026 द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। अतः आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का पात्र है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह 26.09.2025 से जेल/कारागार में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **गोकरन राजपूत** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

1. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

- II. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - IV. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित** के मामले में कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

मार्च 28, 2026

एसए

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।